

अधिसूचना

सं० सं०-०४/आ०१-५५/२०१६...../ राँची, दिनांक-...../

श्री सतीश चन्द्र सिंघु, तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी-सह- जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम-२००५ के प्रावधान अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-८६० दिनांक-२०.१२.२०१७ द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली-२००० के नियम-४३ (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

२. उपर्युक्त संदर्भ में अंकनीय है कि राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक-२४३८१ दिनांक-२४.१०.२०१६ द्वारा अपीलवाद संख्या-१२४०/१५ सच्चिदानन्द बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज मामले में श्री सतीश चन्द्र सिंघु, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जन सूचना पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध दिनांक-१३.१०.२०१६ को सूचना अधिकार अधिनियम-२००६ की धारा-२०(२) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश पारित किया गया था।

३. उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिंघु के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-८६० दिनांक-२०.१२.२०१७ द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

४. उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज से संबंधित था। आरोपित पदाधिकारी द्वारा जन सूचना पदाधिकारी के नाते ससमय आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अंतरित किया गया था। अतः श्री सिंघु के विरुद्ध आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

५. उपर्युक्त के आलोक में श्री सिंघु को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

६. उपर्युक्त निर्णय के साथ ही श्री सिंघु के विरुद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(आदित्य कुमार आनन्द)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-३३...../

राँची, दिनांक-०७-०१-२०...../

प्रतिलिपि:- विभागीय नोडल पदाधिकारी ई० गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव कोषांग

नौ० प्रे० सं०

१६

दिनांक

०८.१.२०

साध्यमिक जिला निदेशालय
झारखण्ड, राँची

दाबरी सं०

५७

दिनांक

०८-०१-२०

सरकार के संयुक्त सचिव।